भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या– 937
दिनांक 05/12/2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

एच-1बी वीज़ा नीति में बदलाव का प्रभाव

937. **डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:**
श्रीमती महुआ मोइत्रा:

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कुछ देशों, विशेषकर अमेरिका द्वारा टैरिफ संरचना और एच-1बी वीजा नीति में हाल ही में किए गए बदलावों के बारे में जानकारी है, जिससे भारतीय निर्यात और कुशल पेशेवरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान उक्त नीति परिवर्तन से प्रभावित होने वाले भारतीय नागरिकों की अनुमानित संख्या कितनी है तथा आगामी वर्षों में इससे किसके प्रभावित होने की संभावना है;

(ग) भारत के प्रमुख निर्यात क्षेत्रों जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, वस्त्र, फार्मास्यूटिकल्स और इंजीनियरिंग सामान पर उक्त टैरिफ परिवर्तनों का अनुमानित प्रभाव क्या है;

(घ) क्या सरकार ने प्रतिबंधात्मक एच1-बी वीज़ा मानदंडों और अस्वीकृति दरों में वृद्धि का मुद्दा संबंधित विदेशी सरकारों के साथ उठाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार विदेश में भारतीय निर्यातकों और कुशल पेशेवरों के हितों की रक्षा करने और द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय मंचों पर बेहतर व्यापार और वीज़ा व्यवस्था पर बातचीत करने के लिए क्या कदम उठा रही है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
[श्री कीर्तवर्धन सिंह]

(क से ङ) 31 जुलाई 2025 को, अमेरिका ने भारत सहित अधिकांश देशों द्वारा निर्यात की जाने वाली कुछ वस्तुओं पर अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (आईईईपीए) के तहत राष्ट्रीय आपातकालीन अधिकारों का प्रयोग करते हुए पारस्परिक शुल्क लगा दिया। इसके अतिरिक्त, 27 अगस्त 2025 को, भारत द्वारा रूस से तेल के आयात के प्रत्युत्तर में आईईईपीए के तहत चुनिंदा भारतीय निर्यात पर अतिरिक्त 25% यथा मूल्य शुल्क लगाया गया।

इसके साथ, अमेरिका ने इस्पात और एल्यूमीनियम, तांबा, गद्दीदार फर्नीचर और किचन कैबिनेट, सॉफ्टवुड और ऑटोमोबाइल जैसे उत्पादों पर व्यापार विस्तार अधिनियम की धारा 232 के तहत अनेक क्षेत्र-विशिष्ट प्रशुल्क लगाए हैं।
कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों, फार्मास्यूटिकल्स, बुलियन, कुछ इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं, कीमती धातुओं, महत्वपूर्ण खनिजों, रेजिन और प्लास्टिक, कृषि उत्पादों और आईटी सेवाओं सहित कई वस्तुएं और सेवाएं इन प्रशुल्कों के अध्यधीन नहीं हैं।

2024 के व्यापार डाटा के आधार पर, भारत द्वारा अमेरिका को निर्यात माल अर्थात, कुल 86.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर में से लगभग 47.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर, इन अतिरिक्त प्रशुल्कों से संबंधित श्रेणियों के अंतर्गत आता है।

सरकार अमेरिका द्वारा उठाए गए कदमों के निहितार्थों पर निर्यातकों और उद्योग के साथ, उनकी प्रतिक्रिया का आकलन करने के लिए घनिष्ठ परामर्श करती रहती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संपर्क जारी है, जिसमें पारस्परिक रूप से लाभकारी, बहु-क्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार करार (बीटीए) को संपन्न करने के उद्देश्य से बातचीत शामिल है।

19 सितंबर 2025 को, अमेरिकी प्रशासन ने "राष्ट्रपति उद्घोषणा" शीर्षक से दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें नई एच-1बी याचिकाओं पर 100,000 अमेरिकी डॉलर का प्रशुल्क लगाया गया था, यदि याचिकाकर्ता के पास वैध एच-1 बी वीजा नहीं है और वह संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर से आवेदन कर रहा है। ये दिशानिर्देश वैध एचबी वीजा पर पहले से ही अमेरिका में रहने वाले आवेदकों द्वारा दायर याचिकाओं पर लागू नहीं होते हैं। चूंकि उद्घोषणा केवल 21 सितंबर 2025 से प्रभावी हुई, इसलिए भारतीय नागरिकों पर इसके प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए अभी तक कोई तुलनीय डाटा उपलब्ध नहीं है।

इसके अलावा, अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग भी एक भारित चयन प्रक्रिया को लागू करने पर विचार कर रहा है जो आम तौर पर उच्च कुशल और उच्च भुगतान वाले विदेशियों को एच-1बी वीजा के आवंटन के पक्ष में होगा। इन घटनाओं ने इस बात पर चिंता जताई है कि हाल के अमेरिकी नीति परिवर्तन उच्च-कुशल अंतरराष्ट्रीय पेशेवरों के लिए देश के आकर्षण को कम कर सकते हैं, जो संभावित रूप से वैश्विक प्रतिभा को वैकल्पिक गंतव्यों की ओर मोड़ सकते हैं।

हालांकि वीजा से संबंधित निर्णय संप्रभु मामले हैं, फिर भी भारत का मानना है कि कुशल प्रतिभा आवाजाही ने दीर्घकाल से भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में प्रौद्योगिकी प्रगति, नवोन्मेषिता, आर्थिक विकास और धन सृजन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोनों देशों के हितधारक नवाचार संचालित उद्योगों के लिए निरंतर सहायता सुनिश्चित करने से संबंधित चर्चा में लगे हुए हैं। भारत सरकार भारतीय पेशेवरों, एच-1बी वीजा कार्यक्रम के तहत शामिल भारतीय पेशेवरों सहित, की आवाजाही से संबंधित सभी मामलों पर अमेरिकी सरकार के साथ सक्रिय रूप से वार्ता कर रही है।

*****